

प्रेषक,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 12 जनवरी, 2010

विषय: आगामी कुम्भ मेला, 2010 की तैयारी हेतु परिवहन विभाग के अस्थाई प्रकृति के कार्यों हेतु प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1551/कुम्भ मेला/परिवहन विभाग दिनांक 24.3.2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, परिवहन विभाग के प्रस्ताव रु० 40.70 लाख (रु. चालीस लाख सत्तर हजार मात्र) धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए, वित्तीय वर्ष 2009-10 में उक्त धनराशि को व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त कार्यों को इसी सीमा में धनराशि से पूर्ण किया जाएगा एवं लागत में वृद्धि के लिए आगणन का पुनरीक्षण किसी दशा में नहीं किया जाएगा। कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाने सुनिश्चित किये जायेंगे। प्रस्तावित मदों में आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि करके इसी लागत में व्यय किया जायेगा और मेला निधि से कोई और धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किशत का कोषागार से आहरण किया जाएगा।
3. मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
4. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।
5. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, इसके कम में समय-समय पर निर्गत आदेशों एवं मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए ही समस्त अधिप्राप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। नयी अधिप्राप्ति के पूर्व, पूर्व में उपलब्ध सामग्री का पहले पूर्ण उपयोग करने के बाद ही नयी सामग्री/उपकरण आदि का क्रय किया जायेगा और आवश्यकता से अधिक सामग्री की अधिप्राप्ति नहीं की जायेगी ताकि मेले के बाद सामग्री अप्रयुक्त न पड़ी रहे।
7. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार किया जाएगा तथा उस पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाए।
8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
9. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

12. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।
13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित विभागीय अधिकारी एवं मेलाधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।
14. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।
15. उपकरणों/सामग्री के क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पूर्व कुम्भ मेलों में क्रय किए गये उपकरणों का भी पूरा उपयोग किया जाए एवं तदनुसार केवल अतिरिक्त आवश्यक उपकरण ही क्रय किए जाएं। यह भी देख लिया जाए कि यदि उपकरण किराए पर लेना अधिक Cost effective व economical हो तो तदनुसार ही कार्यवाही की जाए।
16. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
17. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, हरिद्वार एवं मेलाधिकारी, हरिद्वार पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1614/IV(1)/2009-39(सा.)/2006-टी.सी. दिनांक 24 नवम्बर, 2009 के द्वारा मेलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखी गई धनराशि रु. 100.00 करोड़ के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तदुस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जायेगा तथा पुस्तांकन तदुस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 36/XXVII(2)/2009 दिनांक 08, जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1811 (1)/IV(1)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कौषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निर्देशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. सहायक परिवहन आयुक्त/नोडल अधिकारी, परिवहन विभाग, हरिद्वार।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।